



ବନ୍ଦାର୍ଯ୍ୟକ ସମ୍ବାଦ

ਬਾਰੋ : 13 ਅੰਕ : 333 ਪ੃ਛ -4 ਦਿਨਾਂਕ 06 ਦਿਸੰਬਰ 2024 ਦਿਨ ਸ਼ੁਕ੍ਰਵਾਰ

हेमा मालिनी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर गिरफ्तारी की निंदा की बीजेपी सांसद ने कहा, मैं स्वयं कृष्ण भक्त हूं और इस्कोन की अनुयायी हूं.

उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट से भाजपा संसद हेमा मालिनी ने बांगलादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी की बुधवार को संसद में निंदा की। लोकसभा में शून्य काल के दौरान हेमा मालिनी ने कहा, ऐसे स्वयं कृष्ण भक्त हूं और इसकॉन की अनुयायी हूं, मैं कृष्ण की पावन नगरी मथुरा की प्रतिनिधि हूं, हम धर्म पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह विदेश नीति का विषय नहीं है, बल्कि हमारी भावना का विषय है। बांगलादेश सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बांगलादेश में चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जो बिल्कुल

गलत है। वह हिंदुओं के खिलाफ हुए अत्याचार के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। वहां स्थिति खराब है। मैंने सरकार से अनुरोध किया है कि वह कार्रवाई करे और हमारे इस्कॉन भक्तों, हिंदू भाइयों को सुरक्षा दे। हम चुप नहीं रह सकते। यह कूटनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं और श्री कृष्ण के प्रति भक्ति से जुड़ा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बंद हो अत्याचार असम के दारांग—उदलगुड़ी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा सदस्य दिलीप सैकिया ने कहा, हम चाहते हैं कि संसद एक प्रस्ताव पारित करे, जिससे बांग्लादेश सरकार को संदेश दिया जा सके कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पूरी तरह



से बंद हो। साल 1971 में बांग्लादेश के गठन के बाद से लाखों बांग्लादेशी मुसलमान असम में घुसपैठ कर चुके हैं और राजनीतिक और चुनावी प्रणाली में निर्णयक कारक बन गए हैं। उज्जैन से भाजपा सांसद अनिल

फिरोजिया ने कहा कि बांग्लादेश में विभ्य कृष्णादास के लिए कोई वकील उपलब्ध नहीं है, जो उनका प्रतिनिधित्व कर सके। वह जीवन के लिए संर्ध कर रहे हैं। इस मामले में भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए।

6 दिसंबर को डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर होगी सरकारी छुट्टी

उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 दिसंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। इस दिन संविधान समिति के अध्यक्ष और देश के पहले कानून मंत्री डॉ. भीम राव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। अखिलेश यादव सरकार की ओर से मंगलवार को अंबेडकर जयंती के मौके पर इसकी घोषणा की गई। गौरतलब है कि साल 1992 में इसी दिन यानी 6 दिसंबर को को कार सेवकों ने बाबरी का विवादित ढांचा ढहाया था। बीएसपी के अंबेडकर डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की विरासत पर अब तक सबसे बड़ी दावेदार बहुजन समाज पार्टी रही है। बीते कई बरसों में 14 अप्रैल का दिन बीएसपी के लिए बहद खास होता था। आंबेडकर जयंती को बीएसपी के कार्यकर्ता धूमधाम से तो मनाते ही थे, मायावती के शासनकाल में तो सरकारी कार्यक्रम भी बड़े स्तर पर आयोजित किए जाते थे। इसे सेलीब्रेशन का शोर कहें या कुछ और, लेकिन इस

बार बीएसपी भीड़ में कहीं गुम नजर आ रही है नेता क्यों जप रहे हैं
अंबेडकर का नाम? मंगलवारको अंबेडकर जयंती पर दलित उत्साहित हो या ना हो, तमाम राजनीति दलों पर इसकी खुमारी साफ नजर आ रही है। कोई अपने कैपेन की शरुआत इस दिन से कर रहा है, तो अंबेडकर के बहाने छुट्टी देकर वोटरों को लुभाने की कोशिश में है। सवाल ये कि आखिर अंबेडकर सभी पार्टियों के लिए अहम क्यों हो गए हैं? दरअसल, आने वाले दिनों में उन राज्यों में चुनाव हैं जहां दलितों की अच्छी खासी तादाद है। इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं, यहां 15 फीसदी दलित आबादी है। साल 2016 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे जहां 23.5 प्रतिशत दलित आबादी है। साल 2017 में पंजाब में भी चुनाव होने हैं जहां सबसे 31.9 फीसदी दलित आबादी का बसरा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति पहले ही तैयार कर ली है। इसी साल यूपी में भी विधानसभा चुनाव होंगे।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने
संभल हिंसा पर बड़ा बयान दिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्थित संभल में हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया था, वही आज बांग्लादेश और संभल में हो रहा है। घटनाओं की प्रकृति और डीएनए एक ही है। उन्होंने कहा कि संभल और बांग्लादेश की घटनाएं एक जैसी हैं और दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक ही है। सीएम ने यह बयान अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। राम कथा पार्क में रामायण मेले के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, श्याद कीजिए 500 साल पहले अयोध्या कुंभ में बाबर के आदमी ने क्या किया था। संभल में भी यही हुआ था, बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। तीनों का स्वभाव और डीएनए एक ही है। अगर कोई मानता है कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, तो वही तत्व यहां भी आपको सौंपने के लिए ताक में बैठे हैं। उन्होंने सामाजिक एकता को तोड़ने का पूरा इंतजाम कर रखा है। ये बातें करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं, जिनकी विदेशों में संपत्ति है। अगर यहां कोई संकट आया, तो वे भाग जाएंगे और दूसरों को मरने के लिए यहीं छोड़ देंगे।

**ਮਦਰਸਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਮੈਂ ਸ਼ਾਸ਼ਤੋਧਨ ਕਰੇਗੀ ਯੋਗੀ
ਸਰਕਾਰ, ਯੇ ਡਿਗਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਂਗੇ ਮਦਰਸੇ**

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसा अधिनियम 2004 में संशोधन करने का फैसला किया है। इसके तहत मदरसों में 12वीं के बाद मिलने वाली फाजिल (स्नातक) कामिल (पोस्ट ग्रेजुएट) की डिग्रियों को अधिनियम के दायरे से बाहर किया जाएगा। जो मदरसे बारहवीं क्लास से आगे कामिल और फाजिल का प्रमाणपत्र देने देंगे उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी। शासन की ओर से इसे लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लटते हुए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने इस अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए कहा कि मदरसा अधिनियम के सभी प्रावधान संवैधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करते हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में ये भी स्पष्ट किया कि मदरसों में मदरसा अधिनियम और नियमावली सिर्फ बारहवीं क्लास तक ही सीमित रहेगी। इसके आगे कामिल और फाजिल का प्रमाणपत्र देने वाले मदरसों को मान्यता नहीं दी जाएगी क्योंकि उच्च शिक्षा यूजीसी अधिनियम के तहत संचालित होती है। योगी सरकार तैयार कर रही है प्रस्ताव कोर्ट के आदेश से साफ है कि मदरसों से फाजिल और कामिल की डिग्रियां नहीं दी जा सकती, इन डिग्रियों की मान्यता अब केवल यूनिवर्सिटी द्वारा ही दी जा सकती है। जिसके बाद अब यूपी सरकार की ओर से भी इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। शासन की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद जल्द ही मदरसा अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है। बता दें कि यूपी मदरसा अधिनियम 2004 के मुताबिक मदरसा बोर्ड मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं संचालित करता है। इसी के आधार पर यूपी में अशासकीय अरबी, फारसी मदरसों के लिए मान्यता और प्रशासन से सेवा संबंधी नियमावली 2016 में भी तैयार की गई थी। मदरसा अधिनियम में संशोधन के बाद अब मदरसों में 12वीं तक ही शिक्षा देने की अनुमति होगी और उच्च शिक्षा की डिग्री सिर्फ यूनिवर्सिटी से ही मिल सकेगी।

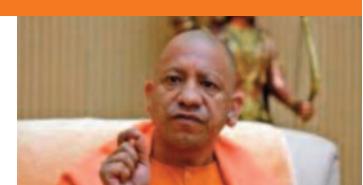
6 दिसंबर को महाराष्ट्र में छट्टी का ऐलान



मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को डॉ. बीआर अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर 6 दिसंबर को 'स्थानीय अवकाश' घोषित किया। डॉ. अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस भी कहा जाता है। उनका निधन 6 दिसंबर, 1956 को दिल्ली में हुआ था। भीमराव रामजी अंबेडकर, को बाबासाहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। वो एक समाज सुधारक और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को सावधानीपूर्वक तैयार करने के लिए संविधान सभा का नेतृत्व किया। गौरतलब है कि मुंबई में बुधवार को महाराष्ट्र भा. जपा विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। जिससे उनके तीसरी बार राज्य का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अजित पवार गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित होने वाले

**क्रिसमस और नए साल पर सीएम योगी
ने अफसरों को दिए संख्या निर्देश**

साल के आखिरी महीने दिसंबर में कई महत्वपूर्ण दिवस हैं, जिनमें 6 दिसंबर के भारतरत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। तो 25 दिसंबर को भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी गाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर रसुशासन दिवसमें अनेक आयोजन प्रस्तावित होने हैं। साथ ही इसी दिन क्रिसमस भी है। इसके बाद 1 जनवरी 2025 को लोग विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारी और अफसर को यह निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार का कहीं भी हुड़दंग न हो। कोई भी कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न करे। सबकी आस्था, सबकी भावना का सम्मान होना चाहिए साथ ही शांति और सौहार्द का माहौल भी बना रहे। सीएम ने कहा कि आगामी 6 दिसंबर को भारतरत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। अनेक संगठनों द्वारा बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जुलूस, सभा आदि आयोजित की जाएगी। ऐसे में कुछ अराजक तत्व माहौल को खाराब करने का प्रयास कर सकते हैं। तिथि की संवेदनशीलता बढ़ाव देने की ज़रूरत है।



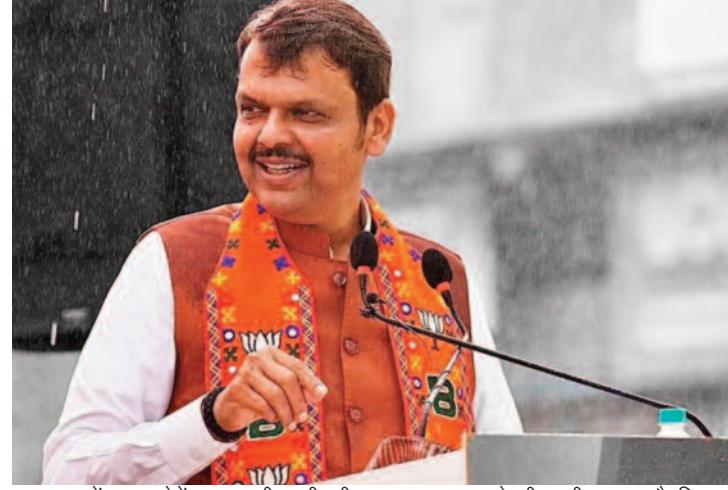
जिलों में सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं। सेक्टर प्रणाली लागू करें और यह सुनिश्चित करें कि कर्ही भी कोई अप्रिय घटना न हो। अतिक्रमण के मामले संवेदनशील हैं, दनशील सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर हुए अतिक्रमण के मामले संवेदनशील हैं, सड़क सभी के लिए है, आवागमन के लिए है, यह बिल्डिंग मटेरियल का सामान रखने, निजी वाहन पार्किंग बनाने, दुकान बनाने अथवा किसी के अनधिकृत कब्जे के लिए नहीं है। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप सार्वजनिक स्थलों पर हुए अतिक्रमण के मामलों में संवाद और समन्वय की नीति अपनाई जाए। सभी जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकध्युलिस अधीक्षक, ग्राम्य विकास विभाग, नगर विकास विभाग के साथ मिलकर स्थानीय निकायों के माध्यम से यह सुनिश्चित कराएं कि प्रदेश में कर्ही भी आवागमन बाधित कर अनधिकृत कब्जा न हो।

पाकिस्तानी समुद्री क्षेत्र में इबा भारत का जहाज

भारत का एक जहाज पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र में डूब गया। जिसके बाद पाकिस्तान ने डूबे भारतीय जहाज के क्रूर सदस्यों की जान बचाई है। पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी (चौं ||) ने बुधवार (4 दिसंबर) को समुद्री बचाव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। भारतीय मालवाहक जहाज डैट ऐ पिनानिपि के डूबने के बाद बीच समुद्र में 12 भारतीय फंस गए थे। चौं || ने बुधवार (4 दिसंबर) को एक बयान जारी कर कहा, "समुद्री बचाव समन्वय केंद्र **MRCC** को भारत के मुंबई **MRCC** का ईमेल मिला। जिसमें डूबे हुए जहाज से बचे लोगों का पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए सहायता का अनुरोध किया गया था।"

जारी बयान के अनुसार, भारतीय कार्गो शिप पाकिस्तान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में डूबा था, जिसके 12 क्रू मेंबर्स बीच समुद्र में फंस गए थे। भारत के अनुरोध पर पाकिस्तान ने शुरू किया बचाव अभियानभारत के अनुरोध पर पाकिस्तान समुद्री एजेंसी ने कई अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर बचाव अभियान की शुरुआत की। **PMS** | ने एक जहाज को जीवित लोगों का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं, स्थानीय समुद्री क्षेत्र में अन्य वाणिज्यिक जहाजों को भी अलर्ट कर दिया गया। साथ ही उनसे बचाव में मदद करने का भी अनुरोध किया गया। समुद्र में फंसे सभी 12 लोगों को बचाया गया। **PMS** | ने जारी

महाराष्ट्र का देवा भाऊ, जो भाजपा में बन सकता है नया मोठा भाई!



महाराष्ट्र में आज देवद्र फडणवीस तो सराबार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि फडणवीस योगी आदित्यनाथ के बाद भाजपा में दूसरे सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जब भी प्रधानमंत्री मोदी के बाद उनके उत्तराधिकारी की चर्चा होती है तो उसमें अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाता है। अब इस फेर हरिस्त में देवेंद्र फडणवीस का भी नाम जुड़ गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव ने न सिर्फ फडणवीस को फिर मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, बल्कि भाजपा की अगली पीढ़ी का सबसे स्थापित नेता भी बना दिया है। देवेंद्र फडणवीस देश के सबसे कम उम्र के पार्शद रहे। वे साल 1992 में महज 22 साल की उम्र में नागपुर के राम नगर वार्ड से पहला नगर निगम चुनाव जीते। इसके बाद मेयर, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष और फिर मुख्यमंत्री बने। पहले फडणवीस अपनी तुनकमिजाजी के लिए भी जाने जाते थे। मीडिया के सामने कभी किसी नेता पर भड़क जाते थे, तो कभी किसी अधिकारी पर। रैलियों में नेताओं पर ऐसे जुबानी हमले करते, जो आमतौर पर सियासत में नहीं होते। एक बार उन्होंने राज ठाकरे को शगली छाप गुंडाश तक कह दिया था। ऐसे वाकयों ने फडणवीस को महाराष्ट्र में भाजपा का फायरब्रांड नेता बनाया। फायरब्रांड नेता से परिपक्व नेता की छवि बनाने में फडणवीस को वक्त लगा। पिछले 32 साल में नागपुर के श्देवाश ने महाराष्ट्र के श्देवा भाऊश तक का सफर तय किया। इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद श्देवा भाऊश के तौर पर उनकी छवि और पुख्ता हो गई। नतीजों के बाद नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के नाम के पोस्टर और होर्डिंग लगे। इनमें फडणवीस को श्देवा भाऊश लिखते हुए शआधुनिक अभिनन्युश बताया। महाराष्ट्र चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस पर श्देवा भाऊश नाम से एक गाना भी बना, जिसमें उन्हें आधुनिक महाराष्ट्र का निर्माता बताया गया। क्या बनेंगे भाजपा में नए श्मोटा भाइ? देवेंद्र फडणवीस की प्रोफाइल की सबसे मजबूत बात ये है कि वह जितन के करीबी हैं, उतने ही भाजपा



बयान में आगे कहा, 'त्रिति प्रतिक्रिया और प्रभावी समन्वय के नतीजतन भारतीय कार्गो शिप के सभी 12 लोगों को बचा लिया गया। जो अंतरराष्ट्रीय SAR दायित्वों को बनाए रखने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए

च्छे। की प्रतिबद्धता को दिखाता है। यह अँपरेशन राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना समुद्र में इमरजेंसी स्थिति का जवाब देने में **PM**। की तत्परता और पेशेवर विशेषज्ञता दिखाता है।'

अजित पवार की बातों में छिपे हैं कई इशारे, यूँ ही नहीं कहलाते सियासत के दादा

नई दिल्लीरु इशारों से मोहब्बत ही नहीं, बल्कि सियासत भी की जाती है... आज महाराष्ट्र में नई सरकार के मुखिया का शपथ ग्रहण समारोह है. उनके साथ दो उपमुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं. इसमें एक नाम तो अजित पवार का तय है, ये हम नहीं खुद अजित पवार कह चुके हैं. बुधवार को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में छब्बे नेता अजित पवार ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि इनका (शिंदे) तो शाम तक समझ आएगा, लेकिन मैं तो शपथ लेने वाला हूं. इस वाकये के जरिये अजित पवार ने कई सियासी संदेश दे दिए. यही कारण है कि अजित को सियासत का शदादाश भी कहा जाने लगा है. अजित पवार की विलयरिटी, भाजपा के साथ रहेंगे जानकार सूत्रों की मारें तो भाजपा में देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा इसलिए भी भारी था, क्योंकि अजित पवार उनके समर्थन में थे. अजित पवार पहले दिन से ही भाजपा के साथ खड़े हैं. एक भी भी पवार की नाराजगी की खबर सामने नहीं आई. 41 सीटें लाकर अजित पवार ने खुद को प्रूव किया और मजबूती से महायुति गठबंधन में डटे हुए हैं. अजित हवा के साथ चलने वाले नेताओं में हैं, उनकी बातों से स्पष्ट है कि वे लंबे समय तक भाजपा का साथ निभाएंगे. शिंदे के बयान से ये भी साफ है कि वे अपनी सियासत एकनाथ शिंदे से अलग देख रहे हैं. वे शिंदे के साथ नहीं, बल्कि भा. जपा के साथ हैं. उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि शिंदे भाजपा के साथ रहें या न रहें, न ही अजित शिंदे के पलटने पर खुद पलटेंगे. वे राजनीति के चतुर सुजान हैं. वे जानते हैं कि शिंदे ने भा. जपा का साथ छोड़ा तो उनकी अहमियत महायुति गठबंधन में बढ़ेगी. नंबर 2 बनने की ताक में अजित महायुति गठबंधन की पिछली सरकार में तीनों दिग्गज पार्टीयों को बराबर मंत्रालय मिले थे. लेकिन इस बार मेरिट के हिसाब से मंत्रालय दिए जाएंगे. जिसकी जितनी सीटें, उसके उतने अधिक मंत्रालय. ऐसे में भाजपा का नंबर एक, शिवसेना का नंबर 2 और छब्बे का नंबर 3 पार्टी बनना तय है. हालांकि, अजित पवार की पार्टी खुद के लिए नंबर दो की पोजीशन मांग रही है, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा. अजित खेमा वित्त मंत्रालय भी चाहता है. अजित पवार का ये कहना— मेरा तो शपथ लेना तय है... बताता है कि वे भाजपा के शिवसेना से अधिक भरोसेमंद साथी हैं. इससे वे भाजपा को भी संदेश दे गए कि शिंदे से ज्यादा मजबूती से महायुति में NCP है.

**बिहार के लोगों को सताएगी कंपकंपाने वाली ठंड,
बारिश को लेकर भी IMD ने जारी किया अलर्ट**

बिहार न्यूज दिसंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी बिहार में ठंड की विश्विति समान्य से कम देखी जा रही है, जबकि मौसम विभाग ने दावा किया था कि इस बार अधिक ठंड होगी। हालांकि अभी शुरुआत में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ताजा अनुमान के अनुसार, एक से दो दिनों में ठंड में काफी बढ़ातरी होगी और आगामी तीन दिनों के बाद कंपकपी वाली ठंड भी होने का की संभावना है। आज गुरुवार को सुबह से पछुआ हवा के प्रवाह में बढ़ातरी हुई है, जिसके कारण अधिक ठंड का असर धीरे-धीरे दिखने लगा है। आगामी 8 और 9 दिसंबर को राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिणी भागों के जिलों में वर्षा की संभावना बन रही है, जिसके कारण ठंड में और ज्यादा इजाफा होगा। 8 दि. संबर को 14 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ 7 दिसंबर को पश्चिम हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा और 8 दिसंबर को उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से आज गुरुवार से लेकर आगामी 7 दिसंबर शनिवार तक पछुआ हवा के प्रवाह के साथ दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी तो वही 8 दिसंबर से दक्षिण बिहार के 14 जिले पटना, नालंदा, नवादा, शेखुपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, गया, जहानाबाद, बक्सर, अरबल भोजपुर, औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास में हल्की बूंदाबांदी या बारिश के साथ बादल छाए रहने और कहीं-कहीं गर्जन की चेतावनी भी है। इसके साथ ही दिन के तापमान में 4 से 5 डिग्री गिरावट भी आएगी। 9 दिसंबर को दक्षिण बिहार में बारिश देगी दस्तक इसके अलावा 9 दिसंबर को भी दक्षिण बिहार के सभी 19 जिले जिनमें भागलपुर, जमुई, मुंगेर, खगड़िया और बांका में भी बूंदाबांदी बारिश के साथ तापमान में गिरावट रहेगी। उत्तर बिहार में कोई चेतावनी नहीं दी गई है, जबकि बुधवार को बीते एक सप्ताह के तापमान की तरह समान्य तापमान दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान डेहरी में 10 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य का औसत अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस और औसत न्यूनतम तापमान 13.02 डिग्री सेल्सियस रहा। कुछ प्रमुख शहरों के न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो पटना में 15.6, गया में 13.5, भागलपुर में 13.7, पूर्णिया में 14.1, मुजफ्फरपुर में 15.6, दरभंगा में 13 डिग्री, मोतिहारी में 12 डिग्री सेल्सियस रहा।

पालतू बिल्ली को मारकर कट्टा खा गई महिला

संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य ओहियो, मदर ऑफ प्रेसिडेंट्स के नाम जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के अब तक 7 राष्ट्रपति ओहियो के रहने वाले थे। लेकिन अमेरिका के नवनीर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ओहियो कुछ खास पसंद नहीं है। चुनाव अभियानों के दौरान अपनी रैलियों ने डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये आरोप लगाते रहे कि हैतीशरणार्थी ओहियो में बिल्लियों को मारकर खा रहे हैं। बता दें कि ट्रंप ये आरोप बेवजह नहीं लगाए थे।

दरअसल, ओहियो में अगस्त महीने में
ऐसा ही एक मामला सामने आया था
जिसमें एक महिला पालतू बिल्ली को
मारकर कच्चा खा गई थी। जिसके बाद
उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और
अदालत ने उसे सजा सुनाई क्या था पूरा
मामला 16 अगस्त को ओहियो के स्प्रिंग
फील्ड से लगभग 270 किलोमीटर दूर
एक महिला ने सड़क के बीच में पालतू
बिल्ली को अपने पैरों से दबाकर उसकी
गर्दन मरोड़ दी। इससे बिल्ली के मर
जाने के बाद उसने बिल्ली को कच्चा
चबा लिया। जब स्थानीय लोगों ने ये
क्रूरता देखी तो उनकी आत्मा कांप गई।
ये क्रूरतापूर्ण घटना को देखकर लोगों ने
पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर

महाकुंभ में होमगार्ड विभाग के 14 हजार

जवान होंगे तैनात, 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद



प्रयागराज में इस बार कुंभ की भव्यता और दिव्यता पहले से काफी अच्छी हो रही है। उत्तर प्रदेश में यह महाकुंभ हो रहा है, इसलिए हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि कि उसकी भव्यता और दिव्यता अच्छे से हो और सभी उसका दर्शन करने आए। क्योंकि शास्त्रों में प्रमाण है की कुंभ में देवताओं का वास होता है। सभी ऋषि मुनि हमारे बहुत ऐसे जो देखने को नहीं मिलते हैं। वह महाकुंभ में देखने को मिलते हैं, उनका आशीर्वाद जनता लेती है तो इसलिए हम लोग का दायित्व बनता है कि उसकी भव्यता और दिव्यता बनी रहे। इसके साथ ही देश और विदेश के लोग यहां उसको देखने आएंगे। लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए महाकुंभ में होमगार्ड विभाग ने 14,100 जवान लगाए हैं। अलग-अलग राज्य में लोगों को आमंत्रित करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तेलंगाना जा रहे हैं। वहीं बृजेश पाठक महाराष्ट्र जा रहे हैं तो नितिन अग्रवाल और सुरेश खन्ना दिल्ली जा रहे हैं। साथ ही धर्मवीर प्रजापति चंडीगढ़ और पंजाब जा रहे हैं। ऐसे ही अन्य मत्रियों की जिम्मेदारी भी अलग-अलग राज्यों में लगाई गई है। अलग-अलग प्रदेशों में जाने का कार्यक्रम 15 दिसंबर के पहले खत्म हो जाएगा। 15 दिसंबर के पहले सभी राज्यों में लोगों को आमंत्रित कर दिया जाएगा। विदेश में भी जाने का कार्यक्रम होना है, पर अभी थोड़े समय बाद उसकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। जिले के सभी सिविल डिफेंस के लोग इसमें काम करेंगे। वहीं होमगार्ड के 14100 लोगों की ऊँटी लगाई गई है, इन सभी को 3 जोन में बांटा गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के खास प्लान महाकुंभ में इस बार करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने की उमीद जताई जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए, इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक ढंग से ट्रैफिक मैनेजमेंट का अध्ययन किया जा रहा है। महाकुंभ की तैयारी को लेकर तीर्थराज प्रयाग के ब्लूटीफिकेशन का काम भी तेज रूपतार से चल रहा है। यहां सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विधिता दिखाने के लिए पूरा इंतजाम किया जा रहा है। चौराहों पर जो भी डिजाइन तैयार किया जा रहे हैं, उनमें हॉर्टिकल्चर एन्वायरमेंट के मद्देनजर ग्रीन बेल्ट भी तैयार किए जा रहे हैं।

भारत के लिए बड़े अवसर

पिछले कुछ वर्षों से सरकार और उद्योग जगत की नीतियों में स्पष्ट झलक रहा है कि हम एक दिन जरूर विकसित भारत के लक्ष्य को अपने दम पर हासिल करने में कामयाब होंगे। भारत की निर्यात उपलब्धियां इसकी उभरती हुई विनिर्माण क्षमताओं, रणनीतिक नीतियों और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। भारत वैशिक निर्यात बाजार में एक प्रमुख देश के रूप में उभरा है जिसने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है। ऐसे में नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम ने बुधवार को कहा कि अमेरिका के नव. निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन समेत तीन व्यापारिक साझेदारों पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की घोषणा से भारत के लिए बड़े निर्यात अवसर पैदा होंगे। घरेलू उद्योग को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। ट्रंप ने पिछले सप्ताह मेकिसको और कनाडा से आयात पर 25 प्रतिशत सीमा शुल्क और चीन से आयात पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की बात कही थी। इस कदम की वजह से अमेरिकी व्यापार में बड़ी रुकावटें आने वाली हैं और इससे भारत के लिए बड़े अवसर पैदा होंगे। अहम है कि ट्रंप ने अक्टूबर 2020 में भी भारत को 'टैरिफ किंग' करार दिया था। टैरिफ राष्ट्रों के मध्य होने वाले व्यापारिक आयात या निर्यात पर लगने वाला सीमा शुल्क है। यह व्यापार के क्षेत्र में बढ़ती वैशिक प्रतिस्पर्द्धा से घरेलू उद्योग को सुरक्षित रखने हेतु लगाया जाने वाला औसत टैरिफ दर 1 विश्व की किसी भी की तुलना में सबसे बावजूद अत्यधिक ते बाधाओं के कारण 3 का केवल 13 वां विजब्कि भारत के निहिस्सा अमेरिका जा कि केंद्र सरकार ने



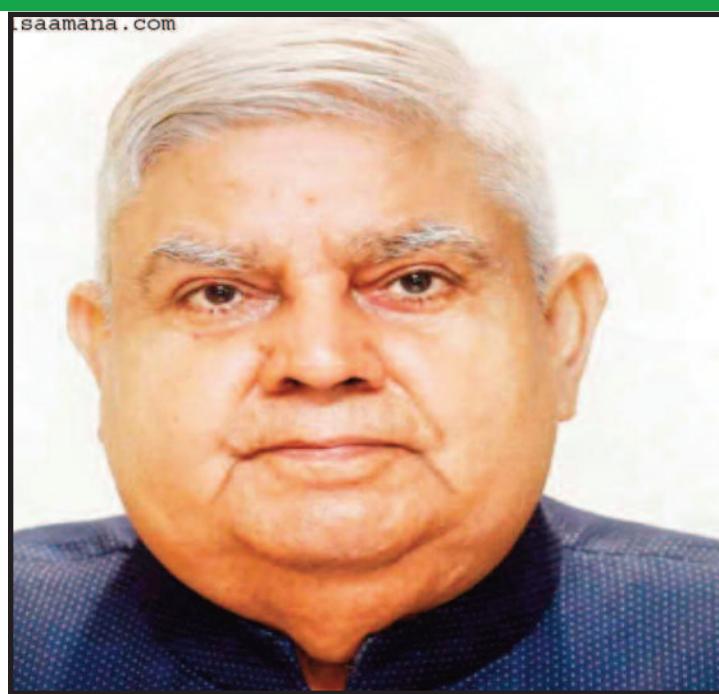
आकर्षित करने और व्यापार करने में आ सानी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों और नीतियों को लागू किया है। निर्यात केंद्रों के रूप में जिलों की पहल प्रत्येक जिले में निर्यात-संभावित उत्पादों की पहचान करती है। विदेशों में भारतीय मिशन भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पिछले वित्त वर्ष में भारत का अमेरिका को निर्यात 77.51

अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 42.2 अरब डॉलर रहा। कुल मिलाकर वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में भारत की यात्रा इसके निर्यात परिदृश्य में उल्लेखनीय उपलब्धियों से चिह्नित है। विभिन्न पहल भारत के व्यापार को बढ़ाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रखांकित करती है, जिससे 2047 तक भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो जाएगा।

किसान आंदोलन का उमेर क्या इससे फायदा होगा?

अपनों की लताड़देश में किसानों की समस्याओं और उसके लिए बार-बार किए जानेवाले आंदोलन को लेकर अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ही मोदी सरकार को आईना दिखाया है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने दिल्ली-नोएडा सीमा पर किसानों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को लेकर मोदी सरकार को खूब खरी-खोटी सुनाई। किसानों को दोबारा सड़कों पर आना पड़ा है इस बाबत उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों से संवाद क्यों नहीं साधा? उनसे चर्चा क्यों नहीं? क्या किसानों और सरकार के बीच बाड़ बनाने की कोशिश हो रही है? उन्होंने बहुत सारे सवालों की झड़ी लगाई। मोदी की बकैतीदस साल पहले मोदी सरकार ने किसानों को लेकर कई बादे किए थे, लेकिन वे सभी बकैती साबित हुए। इसके उलट इस सरकार की नीतियों के कारण देश के आम किसान का अब एक ही काम रह गया है आ। समानी-सुल्तानी आपदाओं का सामना करना, जैसे-तैसे खेतों में फसल उगाना, खराब मौसम से होने वाले नुकसान को सहना और बची-खुची शक्ति फसलों के उचित मूल्य पाने के लिए शासकों के खिलाफ लड़ने में खर्च करना। दस साल पहले मोदी सत्ता में आए थे, कृषि को एमएसपी 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' देने के लिए बहुत सारे बादे किए थे। उस समय मोदी हर भाषण में कहते थे कि वह

किसानों की आय दोगुनी करेंगे और कृषि उपज को 'गारंटी मूल्य' देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वह आज तक इस बारे में 'मुँह में दही जमाए बैठे' हैं। इसके उलट, मोदी सरकार ने हर तरह से 'कृषि सुधार कानूनों' का दोष पीड़ित पर मढ़ने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली सीमा पर किसानों के लंबे विरोध प्रदर्शन और उनकी एकजुटता के चलते मोदी सरकार को अंततरु इन काले कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। दमनकारी सरकारवेशक, एमएसपी से लेकर कई अन्य अधिकारों की मांगों को लेकर किसानों के जो सवाल दस साल पहले थे, वही सवाल आज भी हैं। इसीलिए हजारों किसान फिर से सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन मोदी सरकार ने हमेशा की तरह दमन शुरू कर दिया है। किसान नेता राजेश टिवैहृत समेत करीब ७०० आदोलनकारी किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसीलिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्र के सत्ताधारियों को आड़े हाथों लिया है। किसानों के सड़कों पर उतरने से पहले सरकार ने उनसे बातचीत क्यों नहीं की? यही सवाल उपराष्ट्रपति ने सरकार से पूछा है। वह सही हैं, लेकिन शुरू से ही मोदी सरकार और संवाद का छत्तीस का आंकड़ा है। तीन साल पहले भी किसानों ने इन्हीं मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर जोरदार प्रदर्शन किया था। ठंडे ने



कई किसानों की जान ले ली। फिर भी मोदी सरकार का दिल नहीं पसीजा, बल्कि सरकार द्वारा इस आंदोलन की 'खालिस्तानवादी' साबित करने के कुस्तित प्रयास किए गए। यह सच है कि सरकार ने तीन साल पहले किसान आंदोलन के दबाव में कृषि सुधार कानूनों को वापस ले लिया था, लेकिन सरकार ने किसानों से संवाद करने का शिष्टाचार न तब दिखाया, न बाद में और न अब। इसीलिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अब केंद्र सरकार के कान उमेर्हे हैं और हुक्मरानों को किसानों की जायज मांगों को मानने के लिए उनसे संवाद करने की याद दिलाई है। किसानों से महत्वपूर्ण फिल्मबेशक, क्या यह उपयोगी होगा? क्या हुक्मरानों को अपने दिखाए आईने में अपना चेहरा देखने की हिम्मत होगी? ये सवाल हैं ही। क्योंकि जब किसान अपने अधिकारों की मांग के लिए फिर से दिल्ली की सड़कों पर उतरे, तो प्रधानमंत्री मोदी और उनका मंत्रिमंडल संसद के बालयोगी हॉल में फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' की विशेष स्क्रीनिंग का आनंद लेने में मशगूल थे! मोदी सरकार किसान विरोधी है इसका आपको और क्या सबूत चाहिए?

तीन नए आपराधिक कानूनों से लिये व्याय की आस, पीएम मोदी ने जताई उम्मीद

न्याय में देशी केवल लोगों को हताश-निराश ही नहीं करती बल्कि किसी न किसी स्तर पर देश के विकास की गति को भी बाधित करती है। इसके अतिरिक्त देश की छवि को भी खराब करने का काम करती है। जब समय पर न्याय नहीं मिलता तो कानून एवं व्यवस्था का आदर न करने और उसके उल्लंघन के आदी लोगों का दुर्सङ्ग साहस बढ़ता है। तीन नए आपराधिक कानूनों का पूर्ण अनुपालन करने वाले चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने इन कानूनों के माध्यम से त्वरित न्याय हासिल होने की जो उम्मीद जताई, वह पूरी होनी ही चाहिए। इससे ही इन तीनों कानूनों-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सार्थकता सिद्ध होगी। पूरे देश में इन तीनों कानूनों पर इसी जुलाई से अमल शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ उनका अनुपालन करने में सबसे आगे रहा। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चंडीगढ़ से न केवल प्रेरणा लेनी चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इन कानूनों के जरिये लोगों को समय पर न्याय मिले। अभी तो तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम है और इसके चलते निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में पांच करोड़ से अधिक मामले लियते हैं। यदि तीनों आपराधिक कानूनों को अमल में लाकर त्वरित न्याय के सपने को साकार किया जा सके तो यह विश्व का सबसे बड़ा सुधार तो होगा ही, स्वतंत्र भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पुराने आपराधिक कानून अंग्रेजों ने बनाए थे और उनका निर्माण भारत को गुलाम बनाए रखने के द्वारा से किया गया था। यह ठीक है कि समय के साथ उनमें कुछ संशोधन-परिवर्तन किए गए, लेकिन वे औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सके। विडंबना यह रही कि पिछली सरकारों ने न तो अंग्रेजों के बनाए कानूनों से मुक्ति पाने की कोई पहल की और न ही न्याय में देरी को दूर करने के उपाय किए। न्याय में देरी केवल लोगों को हताश-निराश ही नहीं करती, बल्कि किसी न किसी स्तर पर देश के विकास की गति को भी बाधित करती है। इसके अतिरिक्त देश की छवि को भी खराब करने का काम करती है। जब समय पर न्याय नहीं मिलता तो कानून एवं व्यवस्था का आदर न करने और उसके उल्लंघन के आदी लोगों का दुर्साङ्ग पर अमल से एक ओर जहां 60 दिन के अंदर आरोप तय किए जाएंगे, वहां दूसरी ओर सुनवाई पूरी होने के 45 दिन के अंदर फैसला सुनाना आवश्यक होगा। यह शुभ संकेत है कि तीनों आपराधिक कानूनों पर अमल के बाद से कई मामलों में सचमुच समय पर न्याय हुआ है, जैसे कि चंडीगढ़ में वाहन चोरी में मामला दर्ज होने के 75 दिन के अंदर अदालत ने सजा सुना दी। इसी तरह अशांति फैलाने के एक मामले में 20 दिन में सुनवाई करके सजा सुना दी गई। दिल्ली में भी एक मामले में एफआइआर दर्ज होने के 60 दिन के अंदर फैसला आ गया। ऐसा देश भर में सभी मामलों में होना चाहिए। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निचली अदालतों के जिन फैसलों को ऊंची अदालतों में चुनौती दी जाए, वहां भी उनका निस्तारण आनन्द-फानन हो।



**पटरी पर आई महाराष्ट्र की
राजनीति, शिवसेना के
भाजपा के साथ बने रहने
की गारंटी**

अवधेश कुमार। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने का रास्ता साफ होते ही महाराष्ट्र की राजनीति स्थिर आयाम तक पहुंच गई। विधानसभा चुनाव परिणाम का स्वाभाविक राजनीतिक फलितार्थ यही हो सकता था कि फडणवीस मुख्यमंत्री बनें। 2014 से उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र की राजनीति के जिस दौर की शुरुआत हुई, उस पर 2019 में ग्रहण लगने का कोई स्वाभाविक कारण नहीं था। भा. जपा और शिवसेना दोनों को मिलाकर जनता ने 161 सीटों का बहुमत दिया था, लेकिन उद्घव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी। यहां से महाराष्ट्र की राजनीति अस्वाभाविक, अनैतिक और अस्थिरता के ऐसे दौर में उलझी कि राजनीतिक विचारधारा का सबसे बड़ा संभ्रम कायम हुआ। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना ने सत्ता के नेतृत्व के लिए जिस तरह रंग बदला, उसे जनता की स्थायी स्वीकृति मिलना 2014 से भारत में आरंभ हुई राजनीति के दौर के बीच असाधारण घटना होती। अखिरकार हाल के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति स्वाभाविक विचारधारा की पटरी पर आ गई। एक तरह से जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के अंदर हुए विद्रोह ने ही संदेश दे दिया था कि अस्वाभाविक वैचारिकता को बड़ा वर्ग स्वीकार करने को तैयार नहीं। जब अजीत पवार के नेतृत्व में राकांपा भी भाजपा के साथ आ गई तो साफ हो गया कि महाराष्ट्र के सत्ता समीकरण में कांग्रेस को छोड़कर किसी दल के अंदर सहजता नहीं थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के प्रभावी प्रदर्शन ने फिर से स्वाभाविक राजनीति पर ग्रहण लगाया, लेकिन माना यही गया कि यह भी एक अस्थायी परिघटना है। लोकसभा चुनाव में कई कारकों ने महाराष्ट्र के साथ उत्तर प्रदेश और इससे कम परिमाण में कुछ दूसरे राज्यों में अपनी भूमिका निभाई, जिससे भाजपा के नेतृत्व में राजग की सीटें कम हुईं। लगता है कि स्वयं मतदाताओं ने भी समझा कि उनसे गलती हो गई है। पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में मतदाताओं ने अनुकूल परिस्थितियों एवं समीकरणों की सहजता को देखते हुए जनादेश दिया। चुनाव परिणाम के बाद सरकार गठन में लगभग दो सप्ताह का समय इसी कारण लगा, क्योंकि फडणवीस को नेता के रूप में स्वीकार करने के लिए शिंदे को तैयार करना था या कहें कि उन्हें तैयार होना था। चुनाव परिणाम से इतना तो साफ था कि शिंदे के विद्रोह को शिवसैनिकों ने स्वीकार किया। उन्होंने इतने प्रभावी परिवार से पार्टी को अलग कर उसे विचारधारा की स्वाभाविक पटरी पर लाने की अकल्पनीय भूमिका निभाई। जून 2022 में भाजपा नेतृत्व के सामने सरकार की स्थिरता और सुदृढ़ता के लिए आवश्यक था कि शिंदे को नेतृत्व दिया जाए। भाजपा नेतृत्व ने उन्हें स्थायी रूप से मुख्यमंत्री बनाने का कोई वचन दिया होता तो वह अवश्य इसकी चर्चा करते। यह ध्यान रहे कि पूरे चुनाव अभियान के दौरान कोई भी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश नहीं किया गया। निश्चित रूप से शिंदे के समर्थकों का एक वर्ग फिर से उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता होगा, लेकिन ऐसा होना महाराष्ट्र की रा. जनीति के फिर से अस्थिर होने का कारण बन जाता। शिंदे को भी जनप्रतिक्रिया का आभास हो गया होगा कि उद्घव ठाकरे के विरुद्ध विद्रोह से निर्मित सशक्त नेता की उनकी छहि सरकार गठन में बाधा बनने से कमजोर होगी। ध्यान रहे कि दूसरे साझेदार अजीत पवार के साथ भाजपा को बहुमत मिल गया था और इस कारण शिंदे की अपरिहार्यता नहीं रह गई थी। यह सतह पर दिखने वाला एक पहलू है। भाजपा नेतृत्व को पता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनके लिए शिंदे की शिवसेना के साथ विचारधारा के आधार पर दीर्घकालिक काम करना आवश्यक है।

आवश्यकता है
हिन्दी साप्ताहिक समाचार
पत्र जगनायक समाचार
के लिए जिला व्यूरो चीफमंडल
व्यूरो चीफ ब्लाक, व्यूरो
संवाददाता की
आवश्यकता है।
सम्पर्क करें -
अमित कुमार वर्मा - संभादक
मौ:-8218049162, 827340249

जननायक सम्राट
हिन्दी साप्ताहिक
मालिक, मुद्रक, प्रकाशक
आरती वर्मा द्वारा आशु
प्रिटिंगप्रेस, अचलताल
अलीगढ़ से मुद्रितकारकर
. कार्यालय सरोज नगर
गली नम्बर 5, अलीगढ़
से प्रकाशित
सम्पादक-अमित कुमार वर्मा
सभी विवाद का व्याय क्षेत्र जनपद
अलीगढ़ व्यायलय ही होगा